

"मास्त को जानो" विज़ज़ प्रतियोगिता में राम जूनियर व जे के पब्लिक स्कूल के छात्र रहे अवल

दहकती खबरें। हरदोई। भारत विकास परिषद हरदोई द्वारा "भारत को जानो" विज़ज़ प्रतियोगिता है। मुख्य अंतिम पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया।

सम्पादकीय

भविष्य के अहम सवाल

हरियाणा-जम्मू-कश्मीर में नयी सरकारों के गठन और महाराष्ट्र-झारखण्ड में जोर पकड़ रही चुनावी तैयारियाँ के बीच छत्तीसगढ़ से आई एक जरूरी खबर पर चर्चा की दरकार है। खबर ये है कि सरगुजा जिले के फतेहपुर और साली गांवों के पास करीब 5,000 पेड़ों की कटाई के मामले को लेकर स्थानीय निवासियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों ही पक्षों को चोटें आई हैं। सरकारी ड्यूटी पर तैनात जिन लोगों को शारीरिक चोट पहुंची है, उनका इलाज और मुआवजा दोनों सरकार के जिम्मे पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। दरअसल ये सारा प्रदर्शन और सरकार वे खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने का फैसला भविष्य तेर सवाल से ही जुड़ा है। इंसानों के साथ-साथ जल, जंगल, जमीन और समूची प्रकृति के भविष्य का यह सवाल है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ों को बचाने की लड़ाई लंबे तक से चल रही है। 1,500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह घना जंगल छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का निवास स्थान है। इस घने जंगल के नीचे लाभग पांच अरब टन कोयला ढबा है। इस वजह से पूंजीपतियों और पूंजीवादी सरकारों की गिरावट यहां टिकी हुई है। इस इलाके में खनन बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है, लेकिन स्थानीय लोग इस खनन का लगातार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इसके लिए बड़ा बेदर्दी से जंगल को काटा जा रहा है और यहां की जैवविविधता के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इस समय यहां पर पेड़ों की कटाई राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को दिए गए परस्पर कोल ब्लॉक खनन परियोजना के तहत की जा रही है।

बात गुरुवार का भा पड़ा का कठाइ हाना था, लाकन्बुधगार से ही लोग यहां जमा हो गए। ताकि अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका जा सके। सरकार की तरफ से भी पर करीब 400 पुलिस और वन विभाग के कर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोग लकड़ी के डंडे, तीर और कुल्हाड़ी से लैस थे। प्रदर्शनिकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी चार्ज के बाद उन्होंने जगबी हमला किया। जबकि इन आरोपों से इंकार करते हुए सरगुजा के पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल का कहना है 'ग्रामीण हिंसक हो गए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। उन्हें रोकने और तिर-बितर करने के लिए हमने उचित जवाब दिया।

दिसंबर में हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा पूर्व और केत्र बासन (पीईकेबी) के दूसरे चरण विस्तार के तहत कोयला खदान के लिए पेड़ काटने की कवायद बड़े पैमाने पर हुई थी। तब भी यह काम पुलिस के सुरक्षा घेरे में किया गया था। इससे पहले वन विभाग ने मई 2022 में पीईकेबी चरण-2 कोयला खदान की शुरुआत करने के लिए पेड़ काटने की कवायद आरू की थी।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਾਨ ਕਲਾਵਿਤ ਸੁਰਾ ਕਾਨ ਥਾ।

माहला सशक्तिकरण के लिए यह सहा समय
चेतनादित्य आलोक समाज पर ही इन आयोजनों का रहती है। इसलिए महिने

महिला के कई रूप होते

वह बेटी, बहू, मां, बहन, पत्नी, दादी, नानी आदि रूपों में हमारे इर्द-गिर्द जन्म से मृत्यु तक साए की तरह मौजूद रहती हैं। देखा जाए तो जीवन और समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका किसी-न-किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। इसके बावजूद आधुनिक वैश्विक सामाजिक ढांचे और आर्थिक एवं सांस्कृतिक खांचे में महिलाएं लगातार उपेक्षा, उत्पीड़न, शोषण और दमन का शिकार होती आ रही हैं। यह से लेकर हात्य तक

हा हा हा यह से उपर बाहर तक सरवर दमन और शोषण की चक्की में पिसतीं महिलाओं का वास्तविक महत्व समाज को अभी समझना शेष है। यही कारण है कि वैशिक समाज में महिलाओं के महत्व को प्रतिपादित करने और उन्हें उनका वास्तविक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को विश्व भर की महिलाओं के प्रति आभार जताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 26 अगस्त महिला समाजता दिवस, 22 सितंबर को बेटियों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस एवं 11 अक्टूबर को विश्व भर की बालिकाओं को समर्पित 'विश्व बालिका दिवस' का दुनिया भर में प्रमुखता से आयोजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के विविध रूपों के मानवाधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाने तथा उनके प्रति लोगों को निजी एवं सामूहिक जिम्मेदारियों का स्वरण कराने के

हालांकि ऐसे आयोजनों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि ये सब महज रिवाज बन कर रह गए हैं। न तो हमारी बेटियों, बहुओं, माताओं और बहनों के विरुद्ध बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद दरिद्री करने वाले अपराधियों पर इनका कोई असर होता है और न

किसानों की जिंदगी बेहतर करने के दावे और हकीकत

यह बात 100 प्रतिशत सही व स्टीक साबित हई किसानों ने बताया हम जो सब्ज़ी या बागवानी फसल का रेट मार्केट में देते हैं या नीलामी में बिकता है, वही हमारा माल चिल्लर मार्केट में हमारी बिक्री से 6 से 7 गुना अधिक कीमत में बिकता है जो मैंने सही पाया, इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री का संज्ञान स्टीक लगा। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, किसानों से कौदियों के रेट में बिका बागवानी उत्पाद याने सब्जियां उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने तक कीमतों आसमान कैसे छूटी इसपर तुरंत एक्शन की दरकार है। दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को रबी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में केंद्रीय कृषि मंत्री के संबोधन की करें तो उन्होंने शनिवार को कहा कि सरकार खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद (सब्जियाँ) की कीमतों में भारी अंतर को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, किसान 5 रुपये में सब्जियां बेचता है, तो उपभोक्ता 50 रुपये चुकाता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है, और बीज में जो पैसा जाता है, इसकी साइंटिफिक व्यवस्था बन रही है जिससे किसान को उसके हक का पैसा मिले।

ऐसी है कि तीन चार साल लग जाते हैं किसान तक पहुँचते-पहुँचते।(2)सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। खाद की उपलब्धता भी हो। जो फ़ीडबैक आया है, उसपर हमें चिंता से काम करना है।(3)कैमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हम कैसे कम करें, इस पर हमें धीरे-धीरे ध्यान देना होगा।(4)आर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की ओर जब हम बढ़ेंगे, तब हम धीरे-धीरे इसका उपयोग भी कम कर लेंगे।(5)खाद के लिए केंद्र के साथ राज्य जो भी ध्यान देना होगा। भारी सिस्टी के बाद भी अव्यवस्था के कारण हमारा परिश्रम बेकार हो जाता है।(6)उत्पादन की लागत घटाना हमारा दूसरा लक्ष्य है। पर हेक्टेयर ईल्ड तो बढ़े लेकिन लागत कैसे घटे, इस पर काम हो रहा है। जो चीज हम तय करते हैं, वो कैसे किसान तक जाये, इसके लिए राज्यों का सहयोग चाहिए। उन्होंने बताया कि कृषिचौपाल हम अगले महीने शुरू कर देंगे, इसमें किसान बैठेंगे और वैज्ञानिक बैठेंगे। आगे कहा कि व्यावहारिक रूप से केंद्र और राज्यों के सामने आगर कोई समस्या आती है तो उसे पुरा करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पीएम के नेतृत्व में हर कैबिनेट में किसानों के हित में क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि तीसरे टर्म में तीन गुणी ज़्यादा शक्ति से काम करना चाहता हूँ। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी प्रण लिया कि अकेले पीएम ही तीन गुनी शक्ति से काम नहीं करेंगे बल्कि हम भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कृषि भारतीय

अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी 18 से 19 प्रतिशत तक का योगदान है और 55 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को कृषि ही रोजगार प्रदान कर रही है। कृषि ने ही कोविड में भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और मैं दिन और रात इसे करने की कोशिश करूँगा।

कृषि विभाग के महत्व को समझने की करें तो, सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा काम कोई साधारण काम नहीं है। कृषि विभाग का मतलब है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसानों की जिंदिया कैसे बेहतर बने उसके प्रयास करना। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करने का प्रयास करती है। केंद्र और राज्य दो अलग-अलग नहीं हैं हमारा संघीय ढांचा है, हम दोनों को ही मिलकर काम करना है। कृषि मंत्री के रूप में मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि कोई भी राज्य हो, सभी हमारे लिए बराबर हैं। हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। केंद्र सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है सभी मिलकर काम करेंगे, राज्यों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इस सम्मेलन का संकल्प यही है कि हम मिलकर काम करेंगे। विभिन्न राज्यों से आए कृषि मंत्रियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके अनेकों ठोस सुझाव हम मिले हैं और अनेकों समस्यायें भी बताई

हैं। मैं अधिकारियों से यह कहना चाहता हूँ कि मंत्रियों ने जो समस्याएं रखी हैं उन पर ठोस परिणाम आने चाहिए। राज्यों के मंत्रियों को अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है ताकि समस्याओं पर चर्चा की जा सके। अभी तक हम 17 राज्यों से बात कर चुके हैं और बाकी राज्यों के कृषि मंत्रियों व अधिकारियों को भी हम चर्चा के लिए बुला रहे हैं। किसानों से भी हर सप्ताह संवाद कर रहे हैं। किसानों व किसान संगठनों से प्राप्त राज्यों से संबंधित सुझावों को हम राज्यों को भेजते हैं और केंद्र के विषयों पर विभाग समाधान करते हैं।

कृषि रणनीति के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं। 2019 से तय हुआ कि उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर मुनाफा देना है। खरीदी की भी प्रभावी व्यवस्था हो, इस पर काम हो रहा है। हम दलहन और तिलहन के सबसे उत्पादन भी हैं लेकिन आयत भी हम करते हैं। इसका उत्पादन हमें बढ़ाना है, लेकिन किसान दाम भी देखेगा कि किसमें फायदा है। हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था खत्म की है, चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध को खत्म किया है। दालों की खरीद की व्यवस्था हमने की है। दालों की पूरी खरीदी होगी, किसन चिंता न करें। हम किसी राज्य में 25 प्रतिशत से ज्यादा भी खरीदेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। उन्होंने बताया कि गाँव में टमाटर पैदा हुआ, यहाँ पर आते हुए उसके रेट बढ़ जाते हैं, बीच के ट्रास्पोर्टशन

के खर्च को अगर केंद्र राज्य मिलकर वहन कर लें तो शहर गाले को सस्ता सज्जी मिलेगी और किसान व बेहतर दाम मिल जायेगा। जल खराब होने वाली फसलों विशेष कर सज्जियों को कैसे बचाया जा सके इसके लिए कमेटी बनाई है। हम कृषि का वित्तीकरण करना है कई बार किसी फसल का जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो जाता है राज्य और केंद्र एक प्रयोग करें एक मॉडल फार्म कैसे बने। एक, दो या ढाई एकड़ जमीन में किसान कैसे खेती करें, इस पर काम हो कई किसानों ने बताया है कि एक एकड़ में अच्छा कमा लेता है। अलग-अलग राज्यों में प्रयोग होना चाहिए। हमें परंपरागत खेती का स्वरूप बदलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में इतने एप्रो क्लाइमेटिक ज़ोन हैं कि भारत दुनिया का फूट बास्केट बन सकता है। हम संवेदनशील बनें। किसानों को कई बार नुकसान हो जाता है उस समय हमें किसानों के साथ खड़े होना है। फसल बीमा योजना का पैसा किसानों को समय पर मिल जाना चाहिए। लगातार रिकॉर्ड हो जिससे अधिक से अधिक पैसा किसानों को मिले। अतः अगर हम उत्परक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करेंगे हमें पाएंगे कि किसानों की जिंदगी बेहतर करने का फंडा-किसानों द्वारा रुपए में बेची सज्जी बाजार में 5 रुपए कैसे बिकती है? केंद्र सरकार ने खेत से लेकर थाली तक बागवानी उत्पाद (सज्जियों) की कीमत में भाव अंतर की नज़्र पकड़कर साइंटिफिक व्यवस्था बनाने कमेटी बनाई।

विकसित भारत की ओर बढ़ते देश के कदम

वृत्तान्वयन राज्य
विकसित राष्ट्र बनने की

विकारात राष्ट्र पानी की विद्या भारत तेजी से आगे बढ़ा रहा देश को आत्मनिर्भर बनाने, कास की गति को तेज करने के लिए उठाये गये सकारात्मक रिएण्मां का असर कई क्षेत्रों में खड़ने लगा है। भारत ने जहां 200 ग्रामावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 2014 में भारत की क्षय ऊर्जा क्षमता केवल 75 ग्रामावाट थी 6 जी तकनीक के पेटेंट हम विश्व के छह शीर्ष देशों में मिल हैं। भारत से प्रभावित होकर देशों ने भारत के दवा कानून पनाए हैं। इसी प्रकार कई अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे संकेत मिलने शुरू गए हैं। देश की जनता ने यह बित कर दिया है कि अगर मूलिक प्रयास किया जाय तो कुछ असंभव नहीं है। आज भारत ने विकास की यति रुपिया के

तज विकास का गात दुनिया क

प्रयत्न कर रहा है। विकास भी विरासत के नारे के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य तेजी से हो रहा है। अपने प्रभावी नेतृत्व से भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को देश की एकता के साथ जोड़ने का काम किया है। आज भारत जाग्रत अवस्था में है। मोदी के नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्ज्वल है। आईटी एवं नवाचारों के क्षेत्र में भारत वैश्विक शक्ति बन रहा है। भारत अपने लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कृषि क्षेत्र में आमूल्यचूल परिवर्तन लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। 2014 से पहले कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या शून्य थी जब अब 4000 से अधिक हो गयी है। जिसके कारण देश के किसानों की आय और खुशहाली दोनों बढ़ रही है। सरकार के विकासित भारत 2047 विजन का लक्ष्य भारत को 2047 तक 3.4 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर तक जीडीपी के साथ विकासित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस लक्ष्य में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सुशासन और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है। 2047 के लिए देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में 90 ग्रीन प्रिड क्षमता हासिल करना, 2035 तक बेचे जाने वाले सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना और भारी औद्योगिक उत्पादन को ग्रीन हाइड्रोजन और विद्युतीकरण की ओर लें जाना है। भारत को विकासित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि आज अपना देश जिस स्थित में है उसे उच्च अवस्था

मन पहुंचाना हा आज बुनावा का जा विकसित राष्ट्र है। क्या हमें भारत को उस तरह का विकसित देश बनाना है। क्या इनमें से कोई एक ऐसा राष्ट्र अपने अनुकरण के लायक नहीं है। इस समय हर प्रकार से उच्च देश अमेरिका को माना जाता है लेकिन क्या अमेरिकावासी सुखी हैं नहीं। तकनीकी दृष्टि से उच्च हो रहे हैं लेकिन अन्य समस्याएं विकराल हैं। इसलिए हमें भारत को भारत ही बनाना है अमेरिका नहीं। भारत विकसित बने लेकिन भारत के विचारों और भारत की मेधा शक्ति के आधार पर। आज वैश्विक संकटों से समाधान की खोज में दुनिया भारत की ओर देख रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम भारत को इंग्लॅंड और अमेरिका न बनाने लग जायें। इसलिए विकसित भारत के लिए भारतीय अवधारणा चाहिए। आजादी के बात से हमारे राजनेताओं से यही भूल हुई थी। परिचम से प्रभावित होकर हम अपने दर्शन व ज्ञान की उपेक्षा करने लगे थे। स्वच्छता मिशन के रूप में एक जन आनंदोलन का सूत्रपात्र किया। जन धन की योजना से सबको जोड़ा। देश में डिजिटल क्रान्ति की शुरुआत की। स्टार्टअप के तहत देश में स्वरोजगार के अवसर खुले। मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों का स्वयं का घर होने का सपना पूरा हुआ है। वर्ष 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ। देश गुस्से में था। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पापी पाकिस्तान को मुहरोड़ जवाब दिया। जीएसटी को लागू करके एक बड़ा

2014 के बाद भारत का सांस्कृतिक अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, हैदराबाद में स्टैचू आफ इकवालिटी, काशी विश्वनाथ कारिंडोर, मथुरा वन्दनावन कारिंडोर, केदारनाथ धाम व चार धाम परियोजना के कार्य से सनातन संस्कृति का पुनरोदय का आभास हो रहा है। मोदी के कार्यकाल में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूनिया के कई अन्य देशों में देखने को मिला। अरब देश, रेत का सागर, इस्लामी कायदे कानून का पालन करने वाले देश अबू थाबी में 27 एकड़ भूमि में जब मोदी हिन्दू मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे यह मन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह भारतवर्ष के नवीन सामार्थ्य और आत्मविश्वास का प्रकटीकरण था। मोदी विश्व में हिन्दू शक्ति के प्रतीक बन गये हैं। योग को मान्यता दिलाई। मोदी सरकार बनने के बाद से 150 से अधिक मर्तियां विदेश से वापस आयीं। जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने विश्व को भारतीय संस्कृति का दर्शन कराया। राष्ट्र की प्रगति के लिए सुशासन महत्वपूर्ण होता है। सरकार की योजनाओं के बारे में मोदी सरकार में आम आदमी की धारणा बढ़ली है। पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता था अब अधिकारी व कर्मचारी खुद गरीबों के घरों तक जाकर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। गरीबों तक

महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर विपक्ष की तैयारी

શકાલ અખ્ટસ

2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो कमज़ोर होते नजर आए थे उसकी कुछ भरपाई उन्होंने हरियाणा जीत कर कर ली और अगर अब महाराष्ट्र, झारखण्ड में इंडिया गठबंधन उन्हें नहीं रोक पाया तो वे फिर वापस 2024 लोकसभा चुनाव के पहले की मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे।

यह दोनों विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए मुश्किल हैं। मगर हरियाणा तो कर्णीब-कर्णीब असंभव था। लेकिन कांग्रेस हारी। समझने की बात यह है कि वहां भाजपा नहीं जीती बल्कि कांग्रेस ने खुद अपनी गलतियों से हार को चुना। और यह गलतियां कोई नई नहीं हैं वही पुरानी गुटबाजी, अतिआत्मविश्वास जिसने पिछले दिनों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ हराया उसी की पुनरावृत्ति है। अगर याद करो तो आप इनसे पहले पंजाब, उत्तरखण्ड भी इसी तरह हारे थे। गुजरात भी। 2017 में गुजरात में भाजपा को सौ के नीचे रोक दिया था। खुद 182 में से 77 सीटों पर जीती थी। और 2022 में कांग्रेस ने वहां बेमन से चनाव लड़ा। राहल केवल एक बार

वहां गए। नताजा बाजपा ने रकाई 156 सीटें जीतीं। और कांग्रेस 77 से सीधे 17 पर। यह बैंक ग्राउन्ड बताना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस ने इन हारों से कुछ नहीं सीखा। वह लोकसभा में 99 सीटें लाकर और भाजपा को 240 पर रोककर बहुत इत्मिनान में है। बीजेपी कमज़ोर हुई। प्रधानमंत्री मोदी पर इसका असर पड़ा। लोकसभा में राहुल गांधी उनके सामने गरजे। यहां तक कि जो मोदी कभी दखलंदाजी नहीं करते वे भी नेता प्रतिपक्ष राहुल के चर्चित भाषण कि देश को कमज़ोर किया जा रहा है, नफरत और साम्प्रदायिकता फैलाई जा रही है कि बीच में उठकर बोलने की कोशिश की। मगर राहुल ने उन्हें सठीक जगवाए देते हुए कहा कि- नो नो नो! हिन्दू नहीं भाजपा और संघ हैं जो साम्प्रदायिकता फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गलत बात मत कीजिए। राहुल के उस भाषण ने राजनीति की दिशा बदल दी थी। उसके बाद राहुल ने कहा कि 56 इंच की छाती खत्म हो गई है अब वह मेरे किसी भाषण के दोरान मेरे सामने नहीं ढैंगें। और निश्चित रूप से उसके बाद जिस तरह लेटरल एंटी वापस लेनी पड़ी तक

बिल जापासा का दना पड़ा, ब्राइकार्स बिल वापस लिया, बजट में लाया कैपिटल गैन टैक्स वापस लिया उसने बताया कि मोदी जी अब कमजोर हो रहे हैं। लेकिन मोदी का कमजोर होना और कांग्रेस का ताकतवर होना दोनों अलग-अलग बातें हैं। मोदी को कमजोर हुए मगर कांग्रेस अपनी सेहत बनाने के मामले में लापरवाह ही रही। उसकी जीतते जीतते हारने की कमजोरी दूर नहीं हुई। कांग्रेस जम्मू-कश्मीर पर थोड़ा इतराती है। मगर भूल जाती है कि अभी तक की सबसे कम सीटें उसे इस बार मिली हैं। केवल छह। वह तो नेशनल कान्फ्रेंस ने इज्जत बचाई नहीं तो वहां कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई। जम्मू जो उसका पुराना कार्यक्षेत्र था वहां वह बुरी तरह साफ हो गई। केवल एक सीट मिली। पांच कश्मीर ने दी। जम्मू में कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिसमें से एक राजस्थानी सीट पर जीती और भाजपा ने यहां आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 सीटों पर जीत हासिल की। और एक मजेदार तथ्य यह कि नेशनल कान्फ्रेंस ने जम्मू संभाग से 6 सीटें जीतीं।

अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने में असफल रही और जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने में ?शेनल कान्फ्रेंस की कोई खास मदद नहीं कर पाई। 55 विधायकों का समर्थन है। उमर अब्दुल्ला के पास। कांग्रेस के 6 के बिना भी 90 की विधानसभा में बहुमत। 49 विधायक।

कांग्रेस को सोचना होगा। ईवीएम की गढ़बड़ी है। बहुत सवाल हैं मगर सारा दोष उस पर डालकर खुद की गृहबाजी, सही फैसले नहीं लेने, कंजुअल एप्रोच, चुनाव पूर्व तैयारी न करने जैसे कई मुद्दों पर भी कांग्रेस को सोचना होगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती हैं। बीजेपी विषय के वोट कटवाती है, अपने वोट बढ़वाती है यह आरोप पिछले दस सालों से लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर ध्यान नहीं देती। भाजपा के पज्जा प्रमुख पर व्यंग्य करती है, खिल्ली डाढ़ती है मगर यह नहीं देखती कि वे कितना काम करते हैं और भाजपा के लिए उपयोगी साबित हुए। बूथ मैनेजमेंट आज के चुनाव की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गए हैं। मगर कभी सना नहीं कि कांग्रेस बथ मैनेजमेंट, बूथ के अंदर पाल्म एजेन्ट, मतदान के दिन काउन्टिंग एजेन्ट के प्रशिक्षण के लिए कुकुरती हो। मतदान के खत्म हाथ के बाद किस तरह ईवीएम के नंबर लेना है। ईवीएम का क्लोज बटर अपने सामने दबवाना है। इसके बाद उन फार्मों पर जिन पर पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े की संख्या होती है साइन करना है। उसका कापी लेना है और मतगणना पहले तक स्ट्रांग रूम जहाँ ईवीएम मशीने रखी हैं उनकी निगरानी करना है। यह सारे काम अपने करने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग पर आरोप सही हैं। लेकिन विषय को अपनी तरफ से भी को कसर छोड़ना नहीं चाहिए। पहले भी बताया कि कांग्रेस ने तो 2011 में दिल्ली में हुए अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।

मगर उसके बाद दो लोकसभा चुनाव हो गए। और वह विधानसभा। तो जब तक बीजेपी की केन्द्र में सरकार है चुनाव तो तौर-तरीकों में बदलाव होना संभव नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट ने 19 ईवीएम के खिलाफ कोई राहत न दी। तो अब दो ही रास्ते हैं।

